Demonetization: Impact on Indian Economy

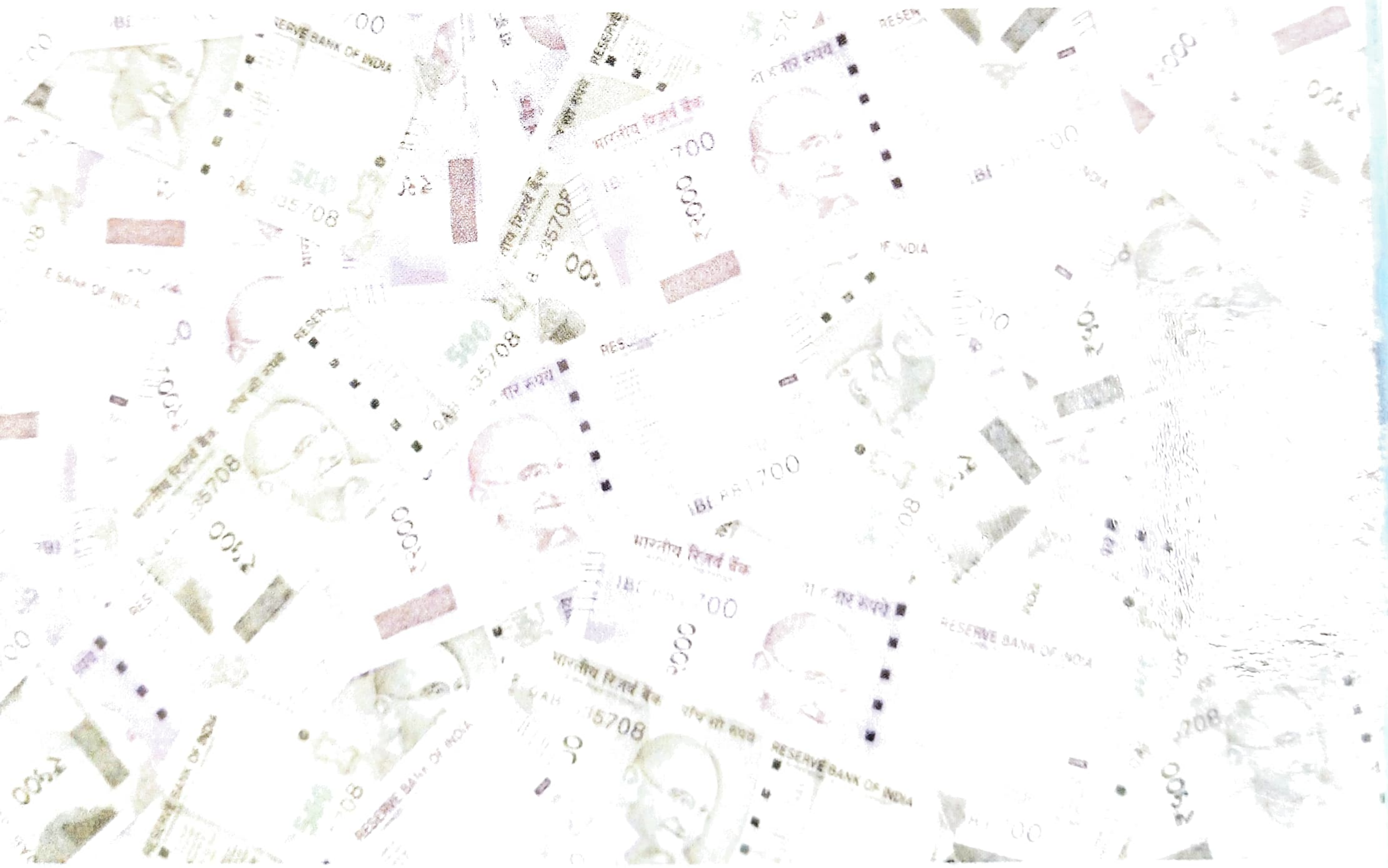

Prof. Sunita Jain

Demonetization:
Impact on Indian Economy
विमुद्रीकरण: भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

Editor : Prof. Sunita Jain

Co-Editor : Prof. Neeraj Topkhane

Editorial Board:

Prof. Girish Mohan Dubey	Dr. Shakti Jain

Dr. Utsav Aanand	Dr. Rupali Saini	Dr. Keshav Tekam

SVN Publishing House

Book Version – 978-81-929700-0-5

Published by:
Swami Vivekanan University , Sagar

Demonetization: Impact on Indian Economy
-Prof. Sunita Jain

SECOND EDITION 2017

ISBN- 978-81-929700-0-5

Published By
Swatantra Computer & Printers
Itwari Ward, Sagar (M.P.)
Ph. 07582-243728 Mob. 9981466528

Laser Composing
Swatantra Computer & Printers
Itwari Ward, Sagar (M.P.)
Ph. 07582-243728 Mob. 9981466528

13. Impact Of Demonetization On The GST — 104
- Ms. Preeti Kashyap

14. Impact Of Demonetization On Information Technology — 110
- Ms. Lata Soni

15. Demonetization: A Long lasting And Optimistic Decision — 116
- Mr. Chaitanya kaushakiya
- Ms. Neha Dubey Kaushakiya.

16. Demonetization And It's Impact Of Indian Economy — 122
- Mr. Bikas Deb

17. विमुद्रीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था — 130
– डॉ.उत्सव आनन्द एवं शोधार्थी – श्री मधुकर इटेवार

18. विमुद्रीकरण का (नोटबन्दी) सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव एक समीक्षात्मक विश्लेषण — 136
– डॉ. बिन्दु श्रीवास्तव

19. भारत में विमुद्रीकरण का प्रभाव — 141
– डॉ. गजेन्द्र कुमार रावत

20. विमुद्रीकरण – कालाधन रोकने का प्रयास — 150
– डॉ. शक्ति जैन

21. अर्थव्यवस्था में विमुद्रीकरण एक लोकतंत्रात्मक आर्थिक सुधार (भारतीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में) — 156
– डॉ. केशव टेकाम
– श्री नीलेश कुमार भास्कर

22. विमुद्रीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था — 166
– डॉ. विशाल मिश्रा

23. विकास के लिए जरूरी – पत्र मुद्रा से दूरी — 171
– डॉ. अंजना चतुर्वेदी

24. भारतीय अर्थव्यवस्था : कमनगदी की ओर बढ़ता एक कदम — 176
– डॉ. वीरेन्द्र सिंह मटसेनिया

25. विमुद्रीकरण : डिजीटल अर्थव्यवस्था हेतु एक अभिनव पहल — 190
– डॉ. एम. एल. सोनी

26. कैशलेस ट्रांजेक्शन, डिजिटल बैकिंग आवश्यकता और माध्यम / उपकरण — 193
– डॉ. भावना यादव

27. प्राचीन काल में मुद्रा का उद्भव एवं विकास: एक विश्लेषण — 200
– डॉ. माधव सिंह रायकवार
– श्री जितेन्द्र कुमार खोब्रागड़े

28. विमुद्रीकरण के वह फायदे जो भारत को बनाएँगे सुपरपावर — 207
– श्रीमती राजकुमारी लोधी

भारतीय अर्थव्यवस्था : कम्नगदी की ओर बढ़ता एक कदम

डॉ. वीरेन्द्र सिंह मटसेनिया

एक नगदरहित अर्थव्यवस्था से अर्थ उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें नगदी के स्थान पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड, ऑनलाइन भुगतान किया जाता है। इस कदम से हम कागजी मुद्रा के स्थान पर डिजिटल मुद्रा की ओर बढ़ रहे है जिससे अर्थव्यवस्था में कालेधन पर रोक भी लगेगी और नगदी के प्रवाह में पारदर्शिता भी आयेगी। हम किसी को भी भुगतान करे वो चाहे, टेक्सी वाला हो, सब्जी वाला हो, या कोई अन्य लेनदेन सभी का भुगतान डिजिटल माध्यम से किया जायेगा। अब हमें भौतिक मुद्रा को जेब में रखने की जरूरत नहीं होगी उसके स्थान पर ई–वॉलेट को रखने की जरूरत होगी और आगे आने वाले समय में क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड दोनों ही निरर्थक हो जायेगें उसके स्थान पर एक स्मार्ट फोन के माध्यम से लेन–देन किये जायेंगे इसी स्मार्ट फोन से ही एटीएम से पैसा का लेन–देन भी संभव होगा।

भारत में इसकी शुरूआत 8 नवम्बर 2016 को प्रधानमंत्री के 500 एवं 1000 रूपये के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया, देश में इन दोनों वर्गों के नोटो से लेन–देन लगभग 85 प्रतिशत से अधिक मूल्य का होता था। इस वजह से नगदी में कमी होना स्वाभाविक ही है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने के लिए लोगों के विवश किया है।

विमुद्रीकरण करने के उद्देश्य –

1. कालाधन को देश से खत्म करना जिससे समान्तर अर्थव्यवस्था को खत्म किया जा सके।

ISBN- 978-81-929700-0-5

2. भ्रष्टाचार को दूर करना क्योंकि नगदी का लेन–देन खत्म होगा तो कार्यालयों में होने वाले भ्रष्टाचार में कमी आयेगी।

3. नकली नोटो पर रोक लगाने के लिए विमुद्रीकरण आवश्यक होता है, क्योंकि जब बाजार में अधिक मात्रा में नकली नोट चलन में आ जाते हैं तो उनको हटाने के लिए विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है।

4. आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए भी विमुद्रीकरण को अपनाया जाता है क्योंकि जब नकली मुद्रा आतंकवादी गतिविधियों में जाने लगे तो उसे रोकने के लिए विमुद्रीकरण किया जाता है।

भारत में नोटबंदी का इतिहास –

भारत में नोटबंदी का इतिहास काफी पुराना रहा है। जैसे 1946 में 500, 1000 एवं 10000 रूपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था। इसके बाद 1970 में कर सुधार समिति बांचू जी की अध्यक्षता में बनी, जिसका भी सुझाव था कि विमुद्रीकरण किया जाये लेकिन इनके सुझाव किसी कारण से सार्वजनिक होने से यह कार्य नहीं हो सका। 1978 में मोरारजी देशाई जी ने 1000, 5000 तथा 10000 रूपये के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया। 2005 में भी भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 500 रूपये की श्रंखला को बदलकर नये 500 रूपये के नोट को प्रिंट किया।

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 27 नवम्बर 2016 को 'मन की बात' में राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए यह संकेत दिये कि भारत को 100 नगदरहित बनाना हमारा सपना है। लेकिन वास्तव में किसी भी देश में 100 प्रतिशत नगदरहित व्यवस्था नहीं आ सकती है लेकिन हम एक कम नगद समाज की ओर जाने की शुरूआत कर सकते है और इसके बाद नगदरहित समाज बनाना दूर कर सपना नहीं होगा अतः हमें कम नगद की ओर चलना और चलने की आदत डालनी ही होगी तभी हम इस मंजिल की ओर बढ़ सकते है। इसकी शुरूआत भी अतिशीघ्र ही करनी होगी और अपनी आदत भी बदलनी होगी।

कम नगद अर्थव्यवस्था के लाभ –

भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से विकास में बढ़त बना सकती है

ISBN- 978-81-929700-0-5

लेकिन उसके समक्ष अनेक समस्या है, जो उसको आगे नहीं बढ़ने देती है ये समस्यायें हैं–

कालाधन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, अवैध सम्पत्ति, जातिवाद और क्षेत्रीयवाद, इत्यादि। जब तक हम इन दुश्चक्रों को तोड़ेंगे नहीं तब तक आर्थिक विकास की गति को आगे नहीं बढ़या जा सकता है। लेकिन इन सभी समस्याओं को खत्म करने में सबसे कारगर उपाय हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में कमनगद व्यवस्था को अपनाना। क्योंकि कमनगद व्यवस्था के होने से जो लेनदेन होंगे उनका विवरण आसानी से रखा जा सकता है। भारत में केवल 10 से 15 प्रतिशत लोग ही गैर–नगदी भुगतानों का प्रयोग करते है जबकि विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जहाँ 40 प्रतिशत तक गैर–नगदी भुगतान का प्रयोग किया जाता है। अतः हम भारतीय अर्थव्यवस्था में गैर–नगदीय को अपनाने से अनेक लाभ हो सकते हैं।

जोखिम में कमी होना – भारत समुचित साइबर सुरक्षा के साथ ऑनलाइन भुगतान अपेक्षाकृत अधिक जोखिम मुक्त माने जाते है जबकि भौतिक नगदी के साथ लेन–देन को हमेशा सुरक्षा की जरूरत होती है। क्योंकि उसके कहीं ले जाना और लाना हमेशा जोखिम भरा होता है।

भुगतान का आसान तरीका – ऑनलाइन बैंकिंग हमेशा सुविधाजनक माना जाता है कोई भी लेनदेन कितना भी बढ़ा क्यों न हो उसके भुगतान में आसानी रहती है। इस प्रकार के लेनदेन में लागत कम आती है और समय की भी बचत होती है।

मुद्रा को बनाने की लागत की बचत– जब हम भौतिक मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो उसको छापना पड़ता है उसके लिए विदेशों से विशेष प्रकार का कागज मांगना पड़ता है और उसके लिए कारखाने स्थापित करने पड़ते है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को नोट छापने में 2015 में 27 विलियन रूपये की लागत आई, कमनगद से इस लागत को कम किया जा सकता है।

अपराधों में कमी आना – हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी अपराध घटित होते है उसके लिये काफी हद तक नगदी का होना है। क्योंकि नगदी होने से नशीले पदार्थों की तस्करी, वेश्यावृत्ति, आतंकवाद, कालेधन को सफेद करने की अनेक समाज विरोधी गतिविधियां चलती रहती है। जब अर्थव्यवस्था में कम नगद की शुरूआत होती है तो इन सब अपराधों पर काबू पाया जा सकता है।

ISBN- 978-81-...

बैंकिंग विकास के लिए अच्छा कदम – कम नगदी से बैंकों का कार्य कम होता है इससे बैंक अत्याधुनिक होने लगते है और कम कर्मचारियों से ही अधिक काम किया जा सकता है क्योंकि लेन–देन में ऑनलाइन व्यवस्था होने से बैंकिंग विकास दिखाई देता है।

अधिक स्पष्ट एवं पारदर्शी व्यवस्था – कमनगदी को अपनाने से मौद्रिक व्यवस्था अधिक स्पष्ट एवं पारदर्शी हो जाती है। क्योंकि प्रत्येक लेनदेन का स्पष्ट विवरण बैंकों के पास रहता है इससे अपराधों पर रोक लगती है।

आय के स्त्रोतों में वृद्धि – कमनगद व्यवस्था के होने से सरकार के आय के स्रोतों में वृद्धि होती है, क्योंकि इससे कर चोरी रूक जाती है प्रत्येक लेन–देन को दायरे में लाया जा सकता है। भारत में दिसम्बर महीने के बाद लेन–देन अधिक डिजीटल हुये हैं, दुकानदारों द्वारा लेनदेन के लिए स्वाईप मशीनों की अधिक मांग बढ़ी है। आज छोटे छोटे दुकानदार जैसे– चाय वाले, फल वाले, सब्जी वाले, किराने वाले, डेयरी उत्पाद वाले, कपड़ा व्यापारी सभी प्रकार के उत्पाद बेचने वालों में स्वाईप मशीन की मांग बढ़ी है और वे नगद की जगह ऑनलाईन से लेनदेन करने लगे हैं।

नगदरहित अर्थव्यवस्था होने से नगदी साथ रखने का जोखिम कम हो रहा है। दूसरा वित्तीय समावेशन का अधिक सुनियोजित ढांचा सामने आ रहा है। अब सरकार के पास स्रोत बढ़ रहे है इससे सरकार अधिक खर्च करने में सक्षम हो रही है।

कम नगद अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी कदम –

आज सरकार कम नगद की ओर जाने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है साथ ही कमनगदी के फायदे भी लोगों को बता रही है। इससे बैंकों में लगने वाली लाइनों में कमी आ रही है एटीएम के बाहर भी लाइनों में कमी आ रही है। उपभोक्ता के लिए भाग्यशाली ग्राहक योजना की शुरूआत सरकार ने की है इससे ग्राहकों में गैरनगद लेनदेन के प्रति रूचि बढ़ी है। गैर–नगदी लेनदेन पर भाग्यशाली ग्राहकों को इनाम देने की व्यवस्था रखी गई है। इसी प्रकार व्यापारियों के लिए भी डिजीटल व्यापार योजना की शुरूआत की गई है इससे ग्राहकों एवं व्यापारियों में गैर–नगदी लेनदेन के प्रति रूझान बढ़े है और दोनों ही पक्ष अब गैर–नगदी को अपना रहे है।

वित्तीय क्षेत्र में लोगों को साक्षर किया जा रहा है इसके तहत लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे डिजीटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ सकते हैं

उसके लिए हमें क्या करना होगा उसके हमारे देश को क्या फायदे होंगे? ये सब बातों को समाज में बताया जा रहा है। मानव विकास एवं संसाधन मंत्रालय द्वारा लोगों से धन के लेनदेन के लिए डिजिटल (गैरनगद) व्यवस्था को अपनाने का आग्रह किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के निजी एवं सरकारी दोनों ही संस्थान नगदी न ग्रहण करें न ही नगदी में भुगतान करें, अतः पूरे संस्थान को नगदी रहित बनाने का कार्य किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने 30 दिसम्बर 2016 को ऑनलाइन लेनदेन को आसान बनाने के लिए वीएचआईएम नामक ई–वॉलेट एप को लांच किया है। इस एप को आधार से जोड़ा गया है जो मोबाइल के द्वारा भुगतान को आसान बनायेगा। इसके लिए ग्राहक का मोबाइल नम्बर बैंक से जुड़ा होना जरूरी है। इस एप से एक समय में केवल एक खाता ही जोड़ा जा सकता है जिन ग्राहकों के दो खाते हैं तो उस ग्राहक को दोनों खातों के लेनदेन के लिए एक खाते से दूसरे खाते में जाना होगा। रूपे कार्ड भारतीय डेविट या क्रेडिट कार्ड जैसा ही है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने जन–धन योजना के अन्तर्गत रूपे कार्ड को शुरू किया है। इस कार्ड धारक को बैंक ने एक लाख रूपये का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। करोड़ों गरीबों के पास रूपे डेविट कार्ड है यह नगद रहित अर्थव्यवस्था से कम समूह को शामिल करने का सफल प्रयास है यद्यपि रूपे का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय समावेशन है और विश्व के आर्थिक मानक बनने के लिए लेनदेन के कारकों पर सही बैठना है जिससे उसकी पहुँच आम लोगों में हो सके।

इसी आधार पर कमनगद की ओर एक ओर कदम उठाया गया है कि सरकार ने एक आधार एप को शुरू किया है इसके तहत किसी व्यक्ति का बैंक खाता आधार नम्बर से जोड़ा जाता है। इस एप को एक वायोमैट्रिक रीडर से जोड़ा जायेगा, जब उपभोक्ता अपनी आधार संख्या दर्ज करेगा और भुगतान के लिये एक बैंक का चुनाव करेगा, इस एप में मोबाइल नम्बर के जुड़े होने की जरूरत नहीं है।

हमारी अर्थव्यवस्था को स्वीडन से कुछ ग्रहण करने की जरूरत है ऐसा माना जा रहा है कि 2020 तक स्वीडन 100 प्रतिशत नगदरहित होने का दावा सही साबित हो सकता है। वह ऐसा देश बनने जा रहा जो नगदरहित देश का नेतृत्व करेगा। स्वीडन की 1600 बैंक में से 900 बैंक ऐसी है जो न तो नगद लेती है और न नगदी देती है। स्वीडन में एप के

माध्यम से बैंक से जुड़ते है वे हर समय किसी को भी भुगतान कर सकते हैं। हालांकि स्वीडन और भारत में बड़ा अन्तर दिखाई देता है। स्वीडन में 100 प्रतिशत साक्षरता है हम केवल 75 प्रतिशत ही साक्षर है। भारत की 68 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है जबकि स्वीडन में 14 प्रतिशत ही गांवों में निवास करती है। प्रतिव्यक्ति आय भी भारत से कई गुना अधिक है। ऐसे कहीं आधार है जो भारत को स्वीडन से तुलना नहीं करने देते है लेकिन फिर भी भारत जैसे विशाल देश में वीएचआईएस जैसे एप को लाकर बड़ी प्रगति की है। भारत की बड़ी समस्या आबादी अधिक होना, जो तकनीकी को बेहतर तरीके से नहीं जानती है। भारत ने गैर–नगदी की ओर कदम तो बढ़ाने शुरू कर दिये है जैसे सरकारी कल्याणकारी योजना के माध्यम से एलपीजी की अनुदान का मिलना और मनरेगा का मजदूरी भुगतान गैर नगद किया जा रहा है। इन सब के बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था आज भी नगदी के सहारे चल रही है। इसमें धीरे–धीरे प्रगति होगी।

भारत बनाम अन्य देशों की स्थिति

भारत से कुछ अन्य देशों की तुलना करने पर पता चलता है कि भारत में व्यवहार में मौजूद मुद्रा कई अन्य विकसित या विकासशील देशों से ज्यादा है। वर्ष 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था में नगदी का चलन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 12.3 फीसदी था, जबकि ब्राजील में यह आंकड़ा 3.8 फीसदी, दक्षिण कोरिया में 5.6 फीसदी और स्वीडन में 1.7 फीसदी था।

वर्ष 2016 में भारत में 68 फीसदी से भी ज्यादा लेन–देन नगदी में हुए, जो दुनिया के बाकि देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। हालांकि, इंडोनेशिया और रूस में नगदी लेन–देन भारत से भी ज्यादा है। थाइलैण्ड, ब्राजील और चीन जैसे विकासशील देशों में भुगतान के लिए नगदी का इस्तेमाल भारत के मुकाबले काफी कम है। भारत में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी कई विकसित और विकासशील देशों की तुलना में काफी कम हो रहा है।

स्वीडन संसार के देशों में नगदी का बेहद कम इस्तेमाल करने वाले देशों में प्रमुख है। इस देश में अधिकांश भुगतान, यहां तक कि बसों के टिकट और दान के लिए भुगतान भी इलेक्ट्रानिक माध्यमों से होता है। खुदरा दुकानदारों को सिक्के और नोट लेने से मना करने का कानूनी अधिकार है। स्वीडन में डेबिट कार्ड का इस्तेमाल यूरोप के सकल औसत

ISBN- 978-81-929700-0-5

इस्तेमाल से तीन गुना ज्यादा है। दिलचस्प यह है कि स्वीडन ने इस साल कुछ मुद्रा नोट 20, 50 और 1000 क्रोन को अमान्य कर दिया। साथ ही, यह देश पहले ही ऐलान कर चुका है कि वह जुलाई 2017 तक कुछ और नोटों को अमान्य कर देगा।

जहां तक विकासशील देश केन्या ने सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन भुगतान के लिए उपाय किए हैं। जैसे काउंसिल पार्किंग, निर्माण संबंधी परमिट, राजस्व, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण, पासपोर्ट शुल्क आदि के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था की गई है, ताकि फर्जीवाड़े को कम कर प्रणाली को बेहतर किया जा सके। विश्व बैंक की वैश्विक फिनडेक्स रिपोर्ट के अनुसार, 2014 में केन्या की 58 फीसदी वयस्क आबादी के पास मोबाइल मनी के सक्रिय खाते थे, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। केन्या के केन्द्रीय बैंक के अनुसार, 2015 में वहां 3.1 करोड़ मोबाइल मनी ग्राहक और 144000 एजेंट थे। केन्या ऐसा उदाहरण है, जहां ऑनलाइन भुगतान के प्रचलन में मोबाइल तकनीक और स्मार्टफोन की संख्या में बढ़ोत्तरी का अहम रोल रहा है। हालांकि, यहां क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बेहद कम होने का कारण इंटरनेट की पहुँच का सीमित होना है।

भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की स्वीकार्यता के अलावा यह भी अहम है कि भुगतान के इन साधनों को समाज में प्रवेश करना है। उदाहरण के तौर पर साल 2015 में भारत की मात्र आधी आबादी के पास क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड थे। वहीं स्वीडन में प्रति व्यक्ति कार्ड की औसत संख्या 2.5, कोरिया में 5.5, ब्राजील में 4.1 और चीन में 4 है।

दक्षिण कोरिया में कार्ड की पहुंच अन्य देशों के मुकाबले काफी अधिक है और यह नगदरहित भुगतान प्रणाली की दिशा में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस देश ने वैसे उपभोक्ता को कर में सुविधा देने की प्रणाली शुरू की है, जो कार्ड के जरिये भुगतान करते हैं। सामान्य तौर पर इसका उद्देश्य प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देना है। भारत में कार्ड से भुगतान करने पर बैंक फीस लेते हैं, इससे ग्राहकों के लिए नगदी में भुगतान करने का विकल्प ज्यादा आकर्षक लगता है। साथ ही, भारत की बड़ी आबादी के मुकाबले यहां ब्राजील अेर चीन समेत सभी विकासशील देशों की तुलना में सबसे कम संख्या में प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल हैं।

कमनगदी के प्रचलन वाले देशों में भुगतान के कई अन्य तरीकों

ISBN- 978-81-929700-0-5

का भी प्रयोग बढ़ा है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक मनी टर्मिनल और मोबाइल मनी भुगतान प्रणाली शामिल हैं। भारत में इन तौर–तरीकों के लिए सीमित सुविधा उपलब्ध है। 1.3 अरब की आबादी वाले भारत में 30 जून, 2016 तक मोबाइल फोन के 1 अरब से भी ज्यादा ग्राहक थे। इसके बावजूद कुल गैरनगदी लेन–देन का सिर्फ 0.05 फीसदी हिस्सा ही इलेक्ट्रानिक मनी टर्मिनल्स के जरिये होता है। इस तरह के लेन–देन को मोबाइल फोन से किया जा सकता है। इसका एक कारण भारत में स्मार्टफोन की संख्या और इंटरनेट की पहुंच का अन्य देशों के मुकाबले कम होना है। भारत में 2016 में सिर्फ 17 फीसदी वयस्क लोगों के पास स्मार्टफोन था, जबकि दक्षिण कोरिया और केन्या में यह आंकड़ा क्रमशः 88 फीसदी और 26 फीसदी है। साथ ही, भारत में 2015 में 26 प्रतिशत लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि ब्राजील और चीन का यह आंकड़ा क्रमशः 59.8 प्रतिशत और 50 प्रतिशत रहा। दक्षिण कोरिया और स्वीडन में तो 90 प्रतिशत लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह, भारत में ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रति 100 लोग पर सिर्फ 1.34 है, जबकि स्वीडन में 36.07 और कोरिया में यह 40.25 है।

2011–2015 में चुनिंदा देशों में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल की संख्या (प्रति 10 लाख व्यक्ति पर)

देश	2011	2012	2013	2014	2015
ब्राजील	17811	20561	22146	24837	25241
चीन	3592	5270	7814	11650	16602
भारत	550	695	865	889	1080
स्वीडन	22167	20837	20380	20304	18660
ब्रिटेन	21499	25732	25800	26346	30078

इस हिसाब से भारत सरकार की कमनगदी वाली पहल के लिए आधारभूत संरचना को काफी तेजी से उन्नत करने की जरूरत है। इसके साथ ही, सही नीतियों के जरिये ऑनलाइन लेन–देन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी जरूरत है।

ISBN- 978-81-929700-0-5

अन्य देशों से सीख और भावी योजना

यदि केन्या जैसे विकासशील देश सफलतापूर्वक कमनगदी वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, तो भारत भी तकनीकी आधारित भुगतान के नए उत्पादों का इस्तेमाल बढ़ाकर ऐसी अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ सकता है। इस प्रक्रिया में ऑनलाइन विनिमय में महत्वपूर्ण मोबाइल भुगतान वॉलेट और मोबाईल एप्लिकेशन महत्वपूर्ण विकल्प हैं। यह विशेष तौर पर छोटे कारोबारों या गैर–कॉरपोरेट खिलाड़ियों के लिए उपयोगी है, जो कार्ड स्वीकार नहीं करते और जिन्होंने भुगतान लेने के लिए प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनल नहीं लगा रखा है। उदाहरण के तौर पर स्वीडन में ज्यादातर दुकानदारों और छोटे कारोबारियों ने आईजेट्ल नामक कंपनी की तरफ से विकसित पीओएस और भुगतान एप्लिकेशन को अपनाया। इससे इन कारोबारों पर अच्छे प्रभाव हुये हैं। इसी तरह केन्या में शुल्क और बिलों के भुगतान और यहां तक वेतन लेने के लिए भी एम–पेसा का इस्तेमाल किया जाता है। भारत में नगदरहित लेन–देन को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम, सीसीएवेन्यू, पेयू जैसे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की इकाईयों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

कुछ क्षेत्रों पर हमें तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, उनमें खुदरा और थोक सौदों के लिए नगदी भुगतान, असंगठित क्षेत्र में मजदूरी भुगतान और खेतिहर मजदूरों को भुगतान शामिल हैं। असंगठित क्षेत्र में ज्यादातर भुगतान नगद में किए जाते हैं ताकि कर से बचा जा सके या मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान किया जाए। नगदरहित लेन–देन को बढ़ावा देने और असंगठित क्षेत्र को संगठित क्षेत्र के दायरे में लाने के लिए कई तरह के प्रयास किये गये हैं। की गई हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया (एनपीसीआई) ने अगस्त 2016 में एकीकृत भुगतान इंटरफेस की शुरूआत की। इसके तहत मोबाइल एप्लिकेशन के इस्तेमाल के जरिए दो बैंक खातों में धन विनिमय किया जा सकता है। यह उपयोगकर्ताओं को कार्ड के ब्यौरे, अन्य कोड और पासवर्ड के इस्तेमाल के बगैर अलग–अलग लोगों को भुगतान की इजाजत देता है। सरकार ने दिसंबर 2016 में एक अध्यादेश पास किया है, जिसके जरिये मजदूरी भुगतान कानून की धारा 6 में संशोधन किया गया है। इसका लक्ष्य है कि कर्मचारियों का वेतन उनके बैंक खाते में ही जमा हो या इस बावत चैक के

जरिये भुगतान किया जा सके। इसका मकसद लेन–देन को नगदरहित बनाना है। यहां इस बात की चर्चा करना जरूरी है कि स्वीडन ने भी 1960 के दशक में मजदूरी और वेतन के डिजिटल विनिमय के जरिये नगदरहित देश की दिशा में आगे बढ़ने की शुरूआत की थी।

तेलंगाना राज्य का इब्राहिमपुर गांव बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल भुगतान के तौर–तरीकों के इस्तेमाल से पूरी तरह नगदरहित हो चुका है। अन्य गांव भी सफलता की इस कहानी को अपना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गुजरात के अकोदरा गांव को 2015 में एक निजी बैंक ने पूरी तरह से डिजिटल बना दिया। बैंक ने वायरलेस इंटरनेट और भुगतान टर्मिनल जैसी अवसंरचना में निवेश किया है, जिससे गांव के लोगों को आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं मिली हैं। भारत में बाकि जो पहल की जा रही हैं, उनमें मेट्रो ट्रेन जैसे सार्वजनिक परिवहन के साधनों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के प्रणाली को शामिल किया जाना शामिल है। दिल्ली मेट्रो के कुछ स्टेशन साल 2017 में नगदरहित हो जाएंगे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है।

कमनगदी वाली अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ने के लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए–

कार्ड द्वारा भुगतान को सस्ता किया जाये – कार्ड या डिजिटल प्रणाली के जरिये भुगतान नकद भुगतान की तुलना में खर्चीला नहीं होना चाहिए। बैंक अक्सर ऑनलाइन भुगतान या इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए शुल्क काट लेते हैं। इससे ऑनलाइन भुगतान के तौर–तरीकों को चोट पहुंचती है, क्योंकि नगदी के इस्तेमाल पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है।

निजी सूचना की सुरक्षा – इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान यह सुनिश्चित करता है कि सभी लेन–देन और उपभोक्ता संबंधी सूचना दर्ज हो। इससे निजता के हनन का खतरा हमेशा बना रहता है। उदाहरण के तौर पर स्वीडन में भुगतान प्रणाली के डिजिटाइजेशन के बाद बैंक डकैती के मामले में जबरदस्त कमी आई, लेकिन ऑनलाइन भुगतान में फर्जीवाड़े के मामले बढ़े हैं। अतः हमें आंकड़ों की सुरक्षा और सूचना की निजता को बनाए रखना बेहद जरूरी है। रिजर्व बैंक पहले ही स्मार्ट कार्ड जैसे प्री–पेड भुगतान के उत्पादों से जुड़ी नीतियों को कम करने के लिए एक मजबूत प्रणाली के अलावा शिकायतों का भी तेजी से निपटारा किया जाना चाहिए।

आधारभूत ढांचे को तैयार करना – भुगतान का तरीका अलग–अलग भुगतान टर्मिनल की उपलब्धता, स्वीकार्यता और उससे संपर्क से तय होता है। जैसा कि बताया गया है कि भारत में नगदरहित लेन–देन से निपटने के लिए मौजूद आधारभूत ढांचा अपर्याप्त है। सरकार को आधारभूत ढांचा तैयार करने की जरूरत है। साथ ही, आधारभूत ढांचे को चलाने के लिए क्षमता भी विकसित करती होगी, ताकि देश में बिना किसी परेशानी के नगदरहित लेन–देन हो सके। इससे तहत स्मार्टफोन, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड कनेक्शन आदि उपलब्ध कराना शामिल है। भुगतान का नगद रहित तरीका तकनीक पर आधारित है, इसके लिए इंटरनेट का कनेक्शन मूल शर्त है।

करों में कमी – यह भी जरूरी है कि स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे सूचना और प्रौद्योगिकी उपकरणों पर कर कम किया जाए। इससे लोगों के डिजिटल भुगतान के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ढ़ांचे के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा। यह काफी ज्यादा है। स्मार्टफोन को सस्ता करना पड़ेगा। भारत में निगम कर दुनिया के बाकि देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। भारत में घरेलू कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत और विदेशी कंपनियों के लिए 40 प्रतिशत निगम कर है। इसके अलावा, कंपनियों को अतिरिक्त शुल्कों का भी भुगतान करना पड़ता है। स्वीडन में यह 22 प्रतिशत था और चीन में घरेलू और विदेशी दोनों कंपनियों के लिए यह 25 प्रतिशत था। कर की दर ऊंची होने के कारण चोरी को प्रोत्साहन मिलता है।

अधिक विकसित ई–वाणिज्य नीति – देश में सख्त ई–वाणिज्य नियम जरूरी है, जो नगदरहित भुगतान में ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने कमनगद अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने में सही कदम उठाया है। हालांकि, अन्य देशों का अनुभव यह सिखाता है कि कमनगद अर्थव्यवस्था में अवसंरचना और इसे बढ़ावा देने वाले नियमों की जरूरत होती है। कमनगद अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ने के लिए सरकार, वित्तीय संस्थान और कारोबार को मिलकर काम करना होगा। इसके अलावा, देश में कर की दर कम और इसका ढांचा आसान होना चाहिए। 2017–18 का आम बजट कमनगद अर्थव्यवस्था से संबंधित सरकारी नीतियां पेश करने के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण होगा।

नगद रहित अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियाँ

विमुद्रीकरण ने पूरी अर्थव्यवस्था को कम नकदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन समाज और सरकार के सामने इसने कुछ चुनौतियां भी पेश की हैं। डिजिटल होने के मुद्दे पर भारत में आम सहमति है। लेकिन क्या समुचित बुनियादी ढांचे के बगैर यह संभव है? ग्रामीण क्षेत्रों में, सार्वजनिक बैंकों तथा स्टेट बैंक समूह के एटीएम केवल 20.8 प्रतिशत हैं और निजी क्षेत्र के बैंकों के एटीएम 8.5 प्रतिशत हैं, जो बहुत कम प्रतीत होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम मिलना बहुत मुश्किल हैं। ई–वॉलेट और मोबाइल भुगतान प्रणाली के लिए एक स्मार्टफोन और इंटरनेट की जरूरत होती है, लेकिन भारत की आबादी के चौथाई से भी कम हिस्से के पास स्मार्टफोन हैं, तेज और भरोसेमंद इंटरनेट सेवा महंगी है। सार्वजनिक वाई–फाई, हॉटस्पॉट और मोबाइल फोन बैटरी चार्जिंग स्टेशन भी बहुत ही कम हैं और साइबर सुरक्षा भी चिंता का विषय बनी हुई है। किसी को कैसे भरोसा होगा कि छोटी दुकानों और फेरीवालो के पास कार्ड स्वाईप करना सुरक्षित है और उनके कार्ड का विवरण गोपनीय रहेगा? यदि कार्ड का विवरण चुरा लिया गया तो, किसी व्यक्ति के लिए बड़ी मेहनत से कमाई गयी राशि की भरपाई करने में उसको कई साल लग जायेंगे। अक्टूबर 2016 में 30 लाख से अधिक डेबिट कार्ड के लीक होने का खतरा हो गया था और ग्राहकों से अपने पिन बदलने के लिए कहा गया था। एक महीने बाद जब विमुद्रीकरण के कारण कार्ड से लेन–देन अचानक बढ़ा, तो नेटवर्क पर काफी भार आ गया था, कार्ड मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था और इसी कारण से लोगों को लंबी–लंबी कतारों में घंटों लगना पड़ा।

सरकार का कहना है कि विमुद्रीकरण का प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार से लड़ना है। लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा भ्रष्टाचार का मुख्य स्रोत होता है। दरअसल, उच्च दर्जे के भ्रष्टाचार में नकदी शामिल नहीं होती। अतः भ्रष्टाचार से लड़ने का ऐसा कोई भी प्रयास जिसमें राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता लाना मुश्किल नहीं है, निरर्थक और असफल प्रयास है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने से लेकर बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ–साथ सरकार को इन चुनौतियों से सफलता पाने के लिए नीतियों के निर्धारण पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। भारत एकदम नगदरहित नहीं होगा। पहले सरकार को लोगों की

ISBN- 978-81-929700-0-5

समस्याओं को समझना होगा और यह सोचना होगा कि उनका समाधान कैसे किया जाए।

100 फीसदी नगदरहित समाज के लक्ष्य को प्राप्त करना कभी–भी संभव नहीं होगा, लेकिन हम कम नकदी वाले समाज से शुरू कर सकते हैं और फिर अधिकांशतः नगदरहित समाज की ओर बढ़ सकते हैं। अधिकांशतः नगदरहित समाज की ओर बढ़ना हमेशा लाभप्रद है। हालांकि कई जगहों पर नकदी फिर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी, खासकर ज्यादातर दूर–दराज के क्षेत्रों तथा अनौपचारिक क्षेत्र में, लेकिन ये लेन–देन भी स्वचालित हो सकते हैं। आने वाली तकनीकों के साथ, ऐसे एप्लीकेशन तैयार करने संभव होंगे, जिसमें बहुत अनौपचारिक खरीद का भुगतान भी खरीददार के बैंक खाते से सीधे काट लिया जायेगा। अगर नकदी का परिसंचरण घटता है और ज्यादातर लेन–देन डिजिटल हो जाता है तो लोग अपने साथ कम नकदी रखेंगे। वित्तीय लेन–देन का डिजिटलीकरण भारत में चल रही समानांतर अर्थव्यवस्था को रोकने का प्रभावशाली साधन साबित हो सकता है। इससे रिकॉर्ड रखने में आसानी हो जाएगी और कर आधार भी बढ़ेगा तथा नकदी साथ रखने की जरूरत कम रहेगी और चोरी की दर भी कम हो जाएगी। जाली मुद्रा और उसका प्रयोग समाप्त हो जाएगा और कालेधन को वैध बनाना कठिन हो जायेगा। आईटी के बुनियादी ढांचे की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी जो कि आजादी के 70 साल बाद भी भारत के पास नहीं है। तथापि, कम नगदी वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना इस बात पर निर्भर करता है कि हम साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धांधली, औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय समावेशन, जागरूकता अभियान और समुचित निवारण प्रणाली जैसे मुद्दों से हम कितने प्रभावशाली ढंग से निपटते हैं।

संदर्भ सूची –

1. मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिये प्रधानमंत्री का देश को संबोधन, जिसका प्रसारण 26–27 नवम्बर को किया गया। http://pmonradio.nic.in/# पर उपलब्ध।
2. http://www.bis.org/cpmi/publ/d155.pdf.
3. http://www.totalpayments.org/2013/07/08/top & 5 & cashless & countries.

4. http://www.trai.gov.in/WriteReadData/WhatsNew/Documents/Indicator_Reports_April_June_01_12_2016.pdf.

5. बीआईएस कंट्री टेबल से आकलनः ीजजचरूध्ध्ूण्इपेण्वतहध्बचउपध्चनइसध्क155णीजउ

6. एम–पेसा मोबाइल फोन आधारित मनी ट्रांसफर, फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेसिंग सर्विस है, जिसे वोडाफोन ने शुरू किया है।